मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णत: पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 25 NOVEMBER TO 1 DECEMBER 2020 • VOLUME- 18 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

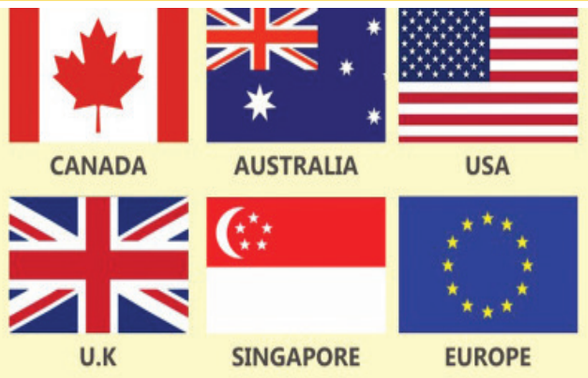

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, बैठक में ममता बनर्जी ने भी लिया हिस्सा

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा की जहां हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बधेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें कर चुके हैं। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है।

प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना के टीके के वितरण की रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल पांच वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इनमें से चार परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में हैं जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है। मंगलवार को देश में एक दिन में कोविड-19 के 37,975 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91.77 लाख के पार चले गए, जिनमें से 86 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे अद्यतन किये गये आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल 91,77,840 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 480 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई।

25 हजार करोड़ रुपए का रोशनी भूमि घोटाला, कई नेताओं और अफसरों के नाम शामिल

■ जम्मू-कश्मीर/न्यूज नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े भूमि घोटाले की अब परते खुलने लगी हैं। बता दें कि 25 हजार करोड़ रुपए के रोशनी जमीन घोटाले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भूमि घोटाले में कई राजनीतिक दलों के नेताओं और नौकरशाहों के नाम शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से गरीबों के घरों को रोशन करने के नाम पर नेता और अधिकारी करोड़ों रुपए की जमीन को हड़प रहे हैं। इसी संबंध में उन नेताओं की पहली सूची सामने आई है जिन्होंने सरकारी जमीन को अपने रिश्तेदारों, भाई-बंधुओं और परिवार की संपत्ति में तब्दील कर दिया है।

इसमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों, व्यापारियों और करीबी रिश्तेदारों के भी नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो महज एक सूची सार्वजनिक हुई है। आगे और भी सूचिओं के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इस घोटाले में ऐसे समय में अहम सुराग सामने आया है जब घाटी में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव होने वाले हैं।

सीबीआई कर रही जांच

रोशनी जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मामले में कई अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। इस घोटाले में कई पूर्व मंत्री, अधिकारियों इत्यादि के नाम सामने आए हैं। इन तमाम लोगों ने रोशनी एक्ट के इस्तेमाल कर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अपने रिश्तेदारों, भाई-बंधुओं और परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर करा दिया था।

आपको बता दें कि इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने ही सीबीआई को सौंपी थी। हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसके तहत आवंटित की गई भूमि के नामांतरण रद्द करने का आदेश सुनाया था और छह माह में भूमि वापस लेने का भी आदेश था।

सामने आए यह नाम

इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू के शामिल होने की खबरें हैं। इसके अतिरिक्त हसीब द्राबू की मां शहजादा भानो, भाई एजाज का नाम भी सामने आया है। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अपने-अपने रिश्तेदारों के नाम भी जमीन हड़प ली। जांच में पीडीपी नेता के अलावा के के अमला और मोहम्मद शफी पंडित का भी नाम सामने आया हैं। के के अमला के श्रीनगर में कई होटला हैं जबकि मोहम्मद शफी मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी रह चुके हैं। इन लोगों ने भी अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन आवंटित कराई थी।

क्या है रोशनी एक्ट ?

साल 2001 में, तब की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि (व्यवसायियों का स्वामित्व का मामला) एक्ट 2001 पारित किया था, जिसे रोशनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत 1990 तक अनाधिकृत तौर पर प्रदेश की भूमि पर कब्जा जारी रखने वाले व्यक्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। सरकार का कहना था कि इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे है लेकिन नेताओं ने जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। फिर 2005 में तब की महबूबा मुफ्ती सरकार ने 2004 के कट ऑफ में और भी ज्यादा छूट दे दी और फिर गुलाम नबी आजाद ने भी कट ऑफ ईयर को साल 2007 तक के लिए सीमित कर दिया था।

एयर इंडिया वन-बी777 की पहली उड़ान में राष्ट्रपति कोविंद ने किया सफर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को 'एयर इंडिया वन-बी777' से चेन्नई रवाना हुए। एयर इंडिया वन-बी777' में राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा कि कोविंद आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करने भी जाएंगे। बयान में कहा गया, '' राष्ट्रपति की 'एयर इंडिया वन-बी777' में यह पहली यात्रा है। विमान में ईंधन की कम खपत होती है और इसमें बी747-400 की तुलना में लंबी रेंज है, जिसका इस्तेमाल इसी प्रकार के वीवीआईपी परिचालन के लिए किया जाता है।'' बयान में बताया गया कि विमान का 'इंटीरियर' अत्याधुनिक है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया है। बयान में कहा गया कि पहली यात्रा के दौरान कोविंद ने पायलटों, चालक दल के सदस्यों और एयर इंडिया तथा भारतीय वायुसेना की पूरी टीम की देश के भीतर और विदेशों यात्रा के दौरान वीवीआईपी परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सराहना की।

स्मार्ट सिटी योजना को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सौंपे केंद्र की सरकार

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

केंद्र में शासित भाजपा सरकार द्वारा देश के 100 शहरों को सौंदर्यकरण के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट को लाँच किया गया जिसका देश के कई शहरों में तो इसका काफी बढ़े स्तर पर लाभ उठाया गया परन्तु कुछ शहरों में इस योजना को हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया जिसमें एक शहर जालंधर जोकि अपने आपको इस योजना के अंतर्गत आने के लिए करवाए गए सर्वेक्षण में तो पहले 100 शहरों में अपना नाम लाने में कामयाब हो गया परन्तु इस योजना को सुचारु ढंग से लागू करवाने में पूरी तरह से विफल रहा इसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं सारा कसूर यहाँ पर आईएएस अफसर की नियुक्तियों का होना अभी तक कोई भी ऐसा अफसर नहीं सरकार द्वारा लगाया गया जो इस योजना को कामयाब कर सके और जो लोगों के सपने को साकार कर सके इसलिए सरकार को स्पोर्ट्स हब वाले इस शहर की स्मार्ट सिटी के तहत हर योजना को लागू करवाने के लिए अपने ही केंद्र के विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क विभाग को सौंप देना चाहिए ताकि उस योजना को सुचारु ढंग से लागू करवाया जा सके और कछुए की चाल पर चल रहे इस प्रोजेक्ट को गति मिल सके।

कपूरथला चौक में किसी भी अधिकारी के निरीक्षण बगैर चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट की मौके की तस्वीरें।

दखल

एफएटीएफ के राडार पर पाकिस्तान

पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के राडार पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पानी मांग रही है और अब जब ग्रे सूची से बाहर निकलना मुश्किल है ऐसे में उसकी स्थिति और बिगड़ेगी। आज की तारीख में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से मिलने वाली सहायता पर ही निर्भर है।

पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के राडार पर है। एफएटीएफ ने पाया है कि पाकिस्तान उसकी तरफ से प्रस्तावित 27 कार्रवाइयों में से 21 में नाकाम रहा और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों और फलह-ए-इंसानियत और जमात-उद-दावा जैसे उनके मुखौटा संगठनों को मिल रही वित्तीय मदद को रोकने में विफल रहा। गौरतलब है कि एफएटीएफ ने पाक को आवंटित 70 लाख डॉलर राशि के इस्तेमाल पर जवाब मांगा था। यह राशि मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन समेत लश्कर और जैश द्वारा संचालित स्कूल, मदरसों, अस्पतालों और एंबुलेंस सेवा के लिए आवंटित हुआ था। उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ दुनिया के उन देशों की सूची बनाती है जिसे मनी लांड्रिंग और आतंकी संगठनों को मिलने वाले धन को रोकने या उसके खिलाफ कदम उठाने में कोताही बरतते हैं। इस आशय की पहली सूची ग्रे तथा दूसरी ब्लैक होती है। ग्रे सूची में शामिल देशों की फंडिंग रोकने के बजाए उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। एफएटीएफ की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस कार्रवाई से अब अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ जैसे वित्तीय संस्थान भी पाक को डाउनग्रेड करेंगे। इससे पहले से ही बदहाल पाक की आर्थिक स्थिति और अधिक तबाह होगी।

गौर करें तो एफएटीएफ जी-7 देशों की पहल पर 1989 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 16 थी, जो 2016 में बढ़कर 37 हो गई। भारत भी इस संस्था का सदस्य देश है। प्रारंभ में इस संगठन का उद्देश्य महज मनी लांड्रिंग पर रोक लगाना था लेकिन 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठनों का वित्त पोषण भी इसकी निगरानी के दायरे में आ गया। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में राडार पर है। 2012 से 2015 में भी वह ग्रे सूची में शामिल रहा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पुनः जून-2018 में ग्रे सूची में डाला और उसे 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा। इसी साल अक्टूबर में दूसरी बार भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के बारे में नई जानकारी देने के उपरांत पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डाल दिया गया। याद होगा गत वर्ष पहले अमेरिका ने पाक को आतंकवाद का गढ़ घोषित कर उसे दी जाने वाली कुल 2,250 करोड़ रुपए की सहायता पर भी रोक लगा दी थी और चेतावनी दिया था कि जब तक वह अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों के खिलाफ असरदार कार्रवाई नहीं करेगा, उसे सैन्य आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। गौर करें तो पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप सिर्फ एफएटीएफने ही नहीं लगाया है। अमेरिकी कांग्रेस की सालाना रिपोर्ट 2016 में भी कहा गया था कि पाकिस्तान आतंकवाद पर दोहरा रुख अपनाते हुए लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है। जबकि अमेरिका 2009 से अब तक उसे चार अरब अमेरिकी डॉलर यानी 300 अरब की मदद दे चुका है। बावजूद इसके पाक ने आतंकी समूहों को मदद देना बंद नहीं किया है। चूंकि एफएटीएफ ने उसके फंडिंग पर निगरानी का शिकंजा कस दिया है ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था का चरमराना तय है। इन परिस्थितियों में उसे न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से झटका मिलेगा बल्कि मूडी, एस एंड पी, और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी उसकी साख में बट्टा लगा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार से उसके लिए फंड जुटाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा।

वैसे भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पानी मांग रही है और अब जब ग्रे सूची से बाहर निकलना मुश्किल है ऐसे में उसकी स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए कि आज की तारीख में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से मिलने वाली सहायता पर निर्भर है। अगर अर्थव्यवस्था में उठापटक हुआ तो फिर पाकिस्तान में निवेश की गति धीमी होगी और निवेशक भाग खड़े होंगे। विदेशी निवेशक और कारोबारी यहां कारोबार करने से पहले हजार बार सोचेंगे। अगर कहीं शेयर बाजार लुढ़कता है और वित्तीय अनिश्चितता की स्थिति उत्पन होती है तो वहां के वित्तीय क्षेत्र का रसातल में जाना तय है। ऐसे हालात में 126 शाखाओं वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड सहित सिटी बैंक एवं ड्यूश बैंक इत्यादि अपना कारोबार समेट सकते हैं। साथ ही आयात-निर्यात प्रभावित होगा और यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल, कॉटन, मार्बल, कपड़े और प्याज सहित कई उत्पादों पर असर पड़ेगा। फिर घरेलू उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना होगा। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसी अराजक आर्थिक स्थिति में चीन पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर अपना हित संवर्धन करने की कोशिश कर सकता है लेकिन यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थियों पर गौर करें तो उत्पादन व खपत दोनों में जबरदस्त गिरावट है और कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी रिकार्ड स्तर पर है। युवाओं की आबादी का बड़ा हिस्सा नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। लाख युवा पलायन को तैयार हैं। लोगों को स्थिरता व सुरक्षा देने वाली सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो आज पाक की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। नए मानकों के आधार पर जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वालों की तादाद 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के केंद्रीय योजना एवं विकास मंत्रालय के मुताबिक देश में गरीबों को अनुपात बढ़कर 30 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। जबकि 2001 में गरीबों की तादाद दो करोड़ थी। आज की तारीख में पाकिस्तान के हर नागरिक पर तकरीबन 1 लाख 30 हजार रुपए कर्ज है। विदेशी लेन-देन और विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी के चलते पहले से ही सिर से उपर चढ़ा पाकिस्तान का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के चालू खाते में घाटे का अंतर पांच प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 12 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुकी है।

पाकिस्तान को अपनी सभी देनदारियां चुकाने के लिए तकरीबन 20 अरब डॉलर की जरूरत है। लेकिन अब जब एफएटीएफ ने उस पर शिकंजा कस दिया है तो वह अपनी देनदारियां किस तरह चुकाएगा कहना कठिन है। गौर करें तो इस हालात व फजीहत के लिए पाकिस्तान स्वयं जिम्मेदार है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही हक्कानी समूह जैसे संगठन अफगानिस्तान में तबाही मचाते हैं। ये आतंकी संगठन कई बार अमेरिका एवं भारतीय दूतावासों पर भी हमला कर चुके हैं। हक्कानी समूह को पाक का प्रश्रय प्राप्त है। इसके अलावा लश्कर तैयबा और जैश भी पाक में शरण लिए हुए हैं। पाक समर्थित हिजबुल और जैश कश्मीर में आतंक मचाने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच अगर एफएटीए पाक को ग्रे सूची से बाहर निकालने को तैयार नहीं है तो यह शांति के लिए आवश्यक है।

विचार

कोरोना काल में भुखमरी का रोग

यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि कोरोना काल में दुनिया के कई देशों में भुखमरी की नौबत आ सकती है। अब तक भुखमरी की समस्या को खत्म करने के प्रयासों का कोई असर नहीं दिखा है। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में प्रयास नहीं हुआ तो हालात खराब होंगे।

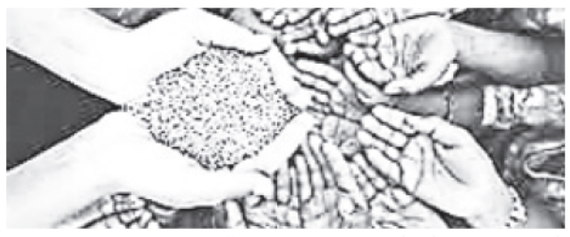

कई दशक से दुनिया के सामने भुखमरी की समस्या चुनौती बन कर उभरी है। अब तक इस संकट से उबरने के उपाय संतोषजनक नहीं रहे हैं। यह समस्या सामान्य स्थितियों में पहले ही गहरा रही थी, लेकिन इस साल मार्च में कोरोना महामारी की वजह से लागू की गई पूर्णबंदी के बाद हालात और ज्यादा जटिल हो गए हैं। अब यूनिसेफ की ओर से जो आशंका जताई गई है, अगर उस पर समय रहते गौर नहीं किया गया और विश्व के समर्थ देशों ने सक्रियता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में खासतौर पर गरीब देशों के कमजोर नागरिक समुदायों को भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ ने कहा है कि अगला वर्ष इस साल की तुलना में कहीं ज्यादा खराब होगा और अगर अरबों डॉलर की सहायता नहीं मिली तो 2021 में भुखमरी के मामले बेतहाशा बढ़ जाएंगे। वैश्विक महामारी से पैदा हुए संकट के बावजूद दुनिया के ज्यादातर समर्थ देशों और उनके नेताओं ने इस साल धन दिया, अलग-अलग मदों में राहत पैकेज दिए। लेकिन यह सरोकार जैसा 2020 में दिखा, अगले साल इसके आसार नहीं दिख रहे।

यही वजह है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम और उसके प्रमुख लगातार वैश्विक नेताओं से इस बारे में बात कर रहे हैं और धन के अभाव में आने वाले वक्त में खराब होते हालात के बारे में दुनिया को आगाह कर रहे हैं। यह एजेंसी विश्व के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों या फिर आपदा के दौरान संकट से घिरे या शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों की मदद करती है। लाखों भूखे लोगों को खाने-पीने के सामान मुहैया करवाने के लिए इसके कर्मचारी कई तरह के जोखिम के बीच काम करते हैं। भुखमरी का सामना करने में इस संस्था के प्रयासों को देखते हुए ही इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। करीब छह महीने पहले संयुक्त राष्ट्र भी कोरोना महामारी के चलते भुखमरी का संकट गहराने की चेतावनी दे चुका है। मगर गरीबी और दूसरे कारणों से इस समस्या की गंभीर स्थिति में कुछ देशों में एक ओर जरूरतमंद आबादी भूख से दो-चार थी, तो दूसरी ओर वहां गोदामों में पड़ा अनाज सड़ कर बर्बाद हो रहा था।

जाहिर है, व्यवस्थागत लापरवाही और सरकारों की इच्छाशक्ति के अभाव ने भुखमरी की समस्या गहराने में ही अपनी भूमिका निभाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई देश अपने स्तर पर वैश्विक भुखमरी से लड़ने के लिए संबंधित संस्थाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि पिछले आठ-नौ महीनों से दुनिया भर में जैसे हालात बने हुए हैं, महामारी का सामना करने के क्रम में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसमें उनसे पहले की तरह मदद की उम्मीद शायद नहीं की जा सकती है। अगर धन की कमी के चलते भुखमरी पर काबू पाने के अभियान बाधित होते हैं, तो इससे एक समस्या से बचाव के क्रम में दूसरे संकट के गहराने के हालात बनेंगे।

देश में बालश्रम का दुश्चक्र

बालश्रम की स्थितियों से निपटने के लिए भारत में संगठन भी काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों के अलावा सरकारी स्तर पर सही कदम उठाए जाएं तो इसकी जल्द रोकथाम की जा सकती है। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जांबिया और मैक्सिको में नगद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी।

बच्चे देश का भविष्य होते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनका बचपन खेलने-कूदने या पढ़ाई-लिखाई के बजाय मजदूरी करते हुए बीतता है। आजाद भारत में आज भी एक करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। हर घंटे दो बच्चों का रेप होता है, चार बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। हर घंटे आठ बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को चुरा कर बाल मजदूरी और बाल वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदा-बेचा जाता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते जहां आर्थिक स्तर पर होने वाले व्यापक नुकसान से काम की स्थिति में गिरावट आई है, वहीं घरेलू आय कम होने और स्कूलों के बंद होने से बालश्रम बढ़ने की आशंका भी बन गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने लॉकडाउन किया था, जो कहीं-कहीं अब भी चल रहा है। इससे व्यापारिक गतिविधियां, कल-कारखाने पूरी तरह बंद रहे, जिससे करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

यूनिसेफ का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में बाल मजदूरी में बढ़ोतरी हो सकती है। गरीबी से त्रस्त परिवार बच्चों को खतरनाक औद्योगिक गतिविधयों में भी काम करने को भेज सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारी संख्या में बच्चों के बचपन पर घातक असर पड़ेगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल राइट टू एजुकेशन फोरम और कैंपेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर की ओर से किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि पूर्णबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों में बाल मजदूरी दर बढ़ी है। गौरतलब है कि बच्चों से काम लेने वाले उन्हें इसलिए काम पर रखते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तुलना में उन्हें वेतन कम देना पड़ता है और उनसे ज्यादा देर तक काम लिया जाता है। आज गांवों की स्थिति ज्यादा खराब है। परिवारों को काम के लिए ज्यादा लोग चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें। अगर हम सुधार के लिए तुरंत कदम नहीं उठाएंगे तो स्थिति और ज्यादा बुरी होगी।

पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में 2150 बच्चों को उक्त सर्वेक्षण में शामिल किया गया था, उनमें 173 दिव्यांग भी शामिल थे। इन दिव्यांग बच्चों में से महज 37 प्रतिशत ऑनलाइन पढ़ाई में सक्षम हैं। पूर्णबंदी के दौरान बीमार पड़ने वाले 11 प्रतिशत बच्चों को कोई चिकित्सीय सहायता भी नहीं मिल सकी। यों भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालश्रम प्रतिबंधित है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण गरीब बच्चों के माता-पिता में लालच और असंतोष का होना है। माता-पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों से मजदूरी कराते हैं, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बालश्रम मे वृद्धि का दूसरा कारण सरकारी स्कूलों में पढाई का स्तर ठीक न होना भी है। भारतीय सरकारी स्कूल अध्यापकों की अनुपस्थिति के मामले में विश्व में युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। स्कूलों के पांचवी कक्षा के अधिकतर बच्चे तीसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। स्कूलों में कौशल विकास बिल्कुल नहीं होता, केवल क्लर्क बनाने वाली रट्टामार पढ़ाई होती है। तो क्यों बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे और क्यों अभिभावक उन्हें स्कूल भेजना चाहेंगे?

नई शिक्षा नीति से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा और शिक्षा व्यवस्था का चरित्र भी बदलेगा, लेकिन उसके लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। सर्वेक्षण के मुताबिक लॉकडाउन के असर से हर राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल मजदूरी में एक सौ पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कियों में बाल मजदूरों की संख्या एक सौ तेरह प्रतिशत बढ़ी है, जबकि लड़कों के बीच इस संख्या में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह होगा कि और ज्यादा बच्चे अधिक मेहनत तथा शोषण वाले काम करने को मजबूर होंगे, लैंगिक असमानता और विकट हो जाएगी। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में बालश्रम पर लगभग सौ देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह चिंता जाहिर की गई थी कि अधिकांश सदस्य देश 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने के अपने लक्ष्य से पीछे ही रहेंगे।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि आज से सात वर्ष बाद भी लगभग एक अरब 21 करोड़ बच्चे अलग-अलग कार्यों में संलग्न पाए जा सकते हैं। अब भी विश्व में पांच से सत्रह वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या एक अरब 52 करोड़ है। नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनीसेफ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लखनऊ में कुल साढ़े तीस हजार बाल मजदूर हैं और कोरोना के कारण इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि यह शहर बालश्रम के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि 2012 से 2016 के बीच बालश्रम में मात्र एक प्रतिशत की कमी देखी गई है।

चिंताजनक बात यह है कि 2012 से 2016 तक बारह वर्ष तक के बच्चों को बालश्रम से मुक्ति दिलाने का कोई खास प्रयत्न नहीं हो सका था। इस अवधि में लड़कियों को ही लड़कों की तुलना में कुछ अधिक मुक्ति दिलाने में सफलता मिल पाई है। बालश्रम का एक प्रमुख कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी निरीक्षकों की कमी होना भी है, जिसके फलस्वरूप लगभग इकहत्तर फीसद बच्चे आज भी कृषि कार्य में लगे हैं, जिनमें से उनहत्तर फीसद बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। आज भी प्रतिदिन 43 लाख बच्चे स्कूल के बजाय काम पर जाते हैं। कोरोना काल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इससे बड़ी त्रासदी भला और क्या होगी कि देश में आज भी सत्रह करोड़ बाल श्रमिक और लगभग 20 करोड़ वयस्क बेरोजगार हैं। ये वयस्क कोई और नहीं, बल्कि बाल श्रमिकों के माता-पिता हैं।

यह विरोधाभास बालश्रम के खत्म होने से ही समाप्त हो पाएगा। बच्चों के विरुद्ध हिंसा, सामूहिक कार्यों, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधन और वंचित बच्चों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति से बालश्रम समाप्त किया जा सकता है। बाल मजदूरी की समस्या का समाधान तभी होगा, जब हर बच्चे को उसका अधिकार उपलब्ध होगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार दिलाने के लिए समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरूरत है। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा श्रमिक दिखे, तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। वैसे, बालश्रम की भयावह स्थितियों से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन भी काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी स्तर पर सही कदम उठाए जाएं तो इसकी जल्द रोकथाम की जा सकती है। बशर्ते हमारे प्रयाय में पूरी तरह से ईमानदारी बरती जाए।

ट्विटर

देश में अन्न का पर्याप्त भंडार है और कोरोना काल में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई है। भारत फिलहाल भुखमरी की समस्या से पीड़ित नहीं है और न होगा।

अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री

भारत में भुखमरी की समस्या से निजात पाने के प्रयास काफी पहले से किए जा रहे हैं। यह किसी एक सरकार के प्रयास का परिणाम नहीं है। इसके लिए सभी सरकारें पात्र हैं।

योगेंद्र यादव, विचारक

सत्यार्थ

जैसा नजरिया, वैसा संसार

एक दिन किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा-गुरुदेव, आपकी दृष्टि में यह संसार क्या है? इस पर गुरु ने उसे एक कथा सुनाई-एक नगर में एक शीशमहल था। महल की हरेक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल कुत्ता महल में घुस गया। महल के भीतर उसे सैकड़ों कुत्ते दिखे, जो नाराज और दुखी लग रहे थे। उन्हें देखकर वह उन पर भौंकने लगा। उसे सैकड़ों कुत्ते अपने ऊपर भौंकते दिखने लगे। वह डरकर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन यह सोचा कि इससे बुरी कोई जगह नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद एक अन्य कुत्ता शीशमहल पहुंचा। वह खुश-मिजाज और जिंदादिल था। महल में घुसते ही उसे वहां सैकड़ों कुत्ते दुम हिलाकर स्वागत करते दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा, तो उसे सैकड़ों कुत्ते खुशी जताते हुए नजर आए। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जब वह महल से बाहर आया, तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहां के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव माना। फिर से आने के संकल्प के साथ वह वहां से रवाना हुआ। इतना कहकर गुरु मौन हुए। शिष्य उत्सुकतावश गुरु की ओर देखने लगे। कहानी पूरी करके गुरु ने शिष्य से कहा-संसार भी कुछ ऐसा ही शीशमहल है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया को पाता है। जो लोग संसार को आनंद का बाजार मानते हैं, वह यहां से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं और जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं, उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। कहने का मतलब है कि जैसा हमारा नजरिया होगा, संसार वैसा ही होगा।

श्रद्धाजंलि

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निगवे खालसा गांव में सांसद संजय मांडलिक ने हवलदार संग्राम शिवाजी पाटिल को श्रद्धाजंलि अर्पित की। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्षविराम उल्लंघन में पाटिल शहीद हो गए थे।

बिहार में हंगामेदार हुई पहले सत्र की शुरुआत

एआईएमआईएम विधायक ने शपथ में नहीं पढ़ा हिंदुस्तान शब्द

पटना, (एजेंसी)। सोमवार से शुरू हुए बिहार की नवगठित 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। पहले दिन सभी नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। इसी दौरान एआईएमआईएम के एक विधायक ने शपथ लेने के दौरान शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की और इसके बजाए भारत पढ़ा। सदन में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव भी पहुंचे। दूसरी तरफ, वैशाली में एक युवती को जिंदा जलाने वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। पांच दिनी यह सत्र 27 नवंबर तक चलेगा।

अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द पढ़ा

बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इंकार कर दिया। इसकी जगह उन्होंने भारत का इस्तेमाल किया। शपथ ग्रहण के दौरान जब एआईएमआईएम विधायक का नाम पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर अपनी आपत्ति जाहिर की। एआईएमआईएम विधायक ने उर्दू भाषा में शपथ लेने अनुमति मांगी थी, जिस पर उन्हें उर्दू वाली स्क्रिप्ट प्रदान की गई।

विधानसभा पहुंचे तेजस्वी

नवगठित बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से आरंभ हो गया। राजद नेता तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विधानसभा के बाहर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

कांग्रेस का प्रदर्शन

इस महीने की शुरुआत में वैशाली जिले में एक 20 वर्षीय लड़की की कथित रूप से जलाने की घटना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पटना में विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

105 नवनिर्वाचित सदस्यों ने पहली बार ली शपथ

17वीं विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र के पहले दो दिन सदस्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं, बाकी के तीन दिनों में विधायी कार्यों को निपटाया जाएगा। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 43.2 फीसदी अर्थात 105 सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। वहीं, 16वीं विधानसभा के 98 यानी कि 40.3 फीसदी सदस्य दोबारा चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा 40 सदस्य यानी कि 16.46 फीसदी ऐसे सदस्य हैं, जो अंतराल (ब्रेक) के बाद जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचे हैं।

न्यूज

कोलंबिया में बंदूकधारियों ने की 13 लोगों की हत्या

मेक्सिको सिटी, (एजेंसी)। कोलंबिया के दो प्रांतों एंटिओक्विया और काकुआ में बंदूकधारियों ने कम से कम 13 लोगों की हत्या कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। बेतनिया नगरपालिका के मेयर कार्लोस मारियो विलदा ने रविवार डब्ल्यू रेडियो कोलंबिया को बताया कि भारी हथियारों से लैस दस लोग ला गेब्रिएला फ्राम में पहुंचे और 14 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जिससे सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

अमेरिका ने शस्त्र नियंत्रण संधि से खींचा हाथ

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका ने सैन्य गतिविधियों की पारदर्शिता को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को लेकर सदस्य देशों के क्षेत्रों में निशस्त्र निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देने वाली शस्त्र नियंत्रण संधि के दायरे से अपने को बाहर कर लिया है।। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन की ओर सदस्य देशों के लिए जारी उस अधिसूचना के मुताबिक उठाया गया है, जिसमें रूस द्वारा समझौते के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया था।

आज होगी अमेरिकी कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा करेंगे। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक श्री बाइडेन के कैबिनेट की नामांकन टीम समीक्षा करने वाली जेन पासकी ने बताया कि श्री बाइडेन अपनी टीम को जनता के सामने पेश करना चाहते हैं और वह इस सप्ताह कैबिनेट सदस्यों की घोषणा करेंगे। सुश्री पासकी ने कहा है कि श्री बाइडेन का कैबिनेट अमेरिका की विचारधारा और पृष्ठभूमि की झलक होगी।

अफगानिस्तान में 15 आतंकी मारे गए

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के मध्य उरुजगन प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 15 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं तथा 13 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी प्रांतीय गर्वनर के प्रवक्ता अहमद शाह साहिल ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकवादियों ने गत रात गिजाब जिले में सुरक्षा बलों की चौकियों पर हमला किया। इसके बाद वायु सेना ने आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों को लक्षित करके हमला किया। इस हमले में एक तालिबानी कमांड सहित 15 आतंकवादी मारे गए तथा 13 अन्य घायल हो गए। इस हमले में दो तालिबानी कमांड सहित 13 अन्य घायल हुए हैं। तालिबानी ने अभी तक इस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी की पैरोल

पेरारीवेलन को चिकित्सा जांच कराने के लिए बढ़ाई अवधि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवेलन की पैरोल को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया, ताकि वह अपनी चिकित्सा जांच करा सके। एजी पेरारीवेलन को मद्रास हाई कोर्ट ने पैरोल दी थी, जो सोमवार को खत्म हो रही थी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता व न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने जाने के दौरान कैदी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वह क्षमा देने के मुद्दे को जनवरी में देखेगा जब वह मामले का निपटान कर देगा। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुनवाई की अगली तारीख पर याचिका में उठाए सभी मुद्दों का निदान करने को कहा। सीबीआई ने 20 नवंबर को दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि पेरारीवेलन को माफी देने पर तमिलनाडु के राज्यपाल को फैसला करना है।

मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी' की जांच का विषय नहीं पेरारीवेलन

सीबीआई ने कहा था कि पेरारीवेलन सीबीआई के नेतृत्व वाली 'मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी' (एमडीएमए) द्वारा की जा रही और जांच का विषय नहीं है। एमडीएमए जैन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 'बड़ी साजिश' के पहलू की जांच कर रहा है। शीर्ष अदालत 46 वर्षीय पेरारीवेलन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने एमडीएमए की जांच पूरी होने तक मामले में उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी की सजा माफी की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दो साल से ज्यादा समय से लंबित रहने पर तीन नवंबर को नाराजगी जाहिर की थी।

माफी देने के संबंध में तमिलनाडु के राज्यपाल को करना है फैसला

सीबीआई ने अपने 24 पृष्ठ के हलफनामे में कहा कि यह तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल को फैसला करना है कि माफी दी जानी है या नहीं और जहां तक राहत की बात है, वर्तमान मामले में सीबीआई की कोई भूमिका नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा कि शीर्ष अदालत 14 मार्च, 2018 को पेरारीवेलन के उस आवेदन को खारिज कर चुकी है, जिसमें उसने मामले में दोषी ठहराए जाने के शीर्ष अदालत के 11 मई, 1999 के फैसले को वापस लिए जाने का अनुरोध किया था। उसने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह निर्दोष है और उसे राजीव गांधी की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी नहीं थी, न तो स्वीकार्य है और न ही विचारणीय है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ता पेरारीवेलन के वकील से पूछा था कि क्या अदालत अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर राज्यपाल से अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल माफी याचिका पर फैसला लेने का अनुरोध कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट दो साल से लंबित सिफारिश से खुश नहीं

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले में अपराधी को माफी देने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम इस क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं हैं कि सरकार द्वारा की गई एक सिफारिश दो साल से लंबित है। तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में 21 मई, 1991 को एक महिला आत्मघाती हमलावर ने एक चुनाव रैली के दौरान विस्फोट किया था, जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई थी।

भारी आलोचना के बीच केरल सरकार ने रोका पुलिस संशोधन अध्यादेश

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। केरल की सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) सरकार की काफी आलोचना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने सोमवार को विवादित केरल पुलिस संशोधन अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। विजयन की सरकार के इस कदम पर 'मीडिया को दबाने' के मकसद से ऐसा करने का आरोप लग रहे थे।

सोमवार को एक विस्तृत बयान में विजयन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर साइबर हमले को देखते हुए हमें यह अध्यादेश लाने पर मजबूर होना पड़ा। इस के चलते कई खुदकुशी और ब्रेक-अप की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन, कई जगहों पर इस पर घोर आपत्ति जाहिर किए जाने के बाद हमने यह फैसला किया है कि इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे।

हर किसी को आलोचना करने का अधिकार

बयान में कहा गया कि हमारे संविधान और कानूनी ढांचे के दायरे में, हर किसी को कड़ी आलोचना करने का अधिकार है। नए संशोधन से उस स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी।

पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है अध्यादेश

इससे पहले, सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने खुद को इस अध्यादेश से अलग करते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। रविवार को अध्यादेश पर भारी आलोचना के बाद मुख्यमंत्री पी. विजयन ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि यह अध्यादेश सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर लाया गया है। नए संशोधन का निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत आशंकाएं निराधार हैं।

इटावा में आर्थिक तंगी से परेशान किसान के बेटे ने की आत्महत्या

इटावा, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बढपुरा इलाके में आर्थिक तंगी के चलते दिल्ली से लौटे किसान के पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जसंवतनगर के पुलिस उपाधीक्षक रमेश चंद्र ने सोमवार को बताया कि नगला भवानी दास निवासी नरोत्तम सिंह का 25 वर्षीय बेटा हुकुम सिंह कोरोना के चलते शनिवार को दिल्ली से घर आया था। रविवार शाम वह घर से बगैर बताए कहीं चला गया था। देर शाम तक वह घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कही नहीं मिला। सोमवार को हुकुम सिंह का शव खेत में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला।

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि सूचना पर बढपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । हुकुम सिंह के पिता नरोत्तम ने बताया कि वह दिल्ली में मौजा बनाने वाली फैक्टरी मे काम करता था और कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण वह शनिवार को ही दिल्ली से घर आया था। परिजनो की मानें तो कोरोना काल में हुकुम सिंह जहां काम करता था, वहाँ से काम छूट गया था इसी कारण आर्थिक तंगी से परेशान हो जाने के वह घर लौट आया था। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

बांग्लादेशी नागरिकों को शामिल करने की योजना पर काम कर रहे थे उमर

दिल्ली हिंसा की चार्जशीट में दावा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के अनुसार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद सीएए के विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को शामिल करने की योजना पर काम कर रहे थे। दरअसल, रविवार को दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक, उमर खालिद के खिलाफ दंगों में गिरफ्तार कई आरोपियों ने 164 के तहत बयान दिए हैं। इनका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस स्पेशल ने उमर खालिद के विरुद्ध किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक, जेएनयू में कथित तौर पर टुकड़े-टुकड़े का नारा देने के बाद उमर खालिद सुर्खियों में आए थे।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह चार्जशीट स्पेशल सेल ने आतंकरोधी कानून यूएपीए के तहत दाखिल की है। इसके साथ ही आईपीसी की कई संगीन धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। चार्जशीट करीब 930 पेज की है।

पहले शरजील और फिर उमर खालिद हुए थे गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है।

खुद को डीआईजी बताने वाले पर मुकदमा दर्ज

सीबीआई ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में की छापेमारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। खुद को सीबीआई का डीआईजी बताकर निजी फायदा उठाने वाले राजीव सिंह नामक एक शख्स के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर अलीगढ़ और बुलंदशहर में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान दो देसी पिस्तौल और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ के मुताबिक, सीबीआई को सूचना मिली थी कि अलीगढ़ और बुलंदशहर इलाके में एक शख्स खुद को सीबीआई का डीआईजी आरआर सिंह बताता है और इस नाम और पद की आड़ में वह फायदा भी उठा रहा है, जबकि सीबीआई के डीआईजी आरआर सिंह का इन जगहों से कोई लेना-देना नहीं था।

अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच

सीबीआई अधिकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी ने सोमवार को शिवपुरी चौराहा तहसील कोल अलीगढ़ और जेवर खेड़ा बुलंदशहर में आरोपी राजीव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के मुताबिक, इस दौरान उसके ठिकानों से दो देसी पिस्तौल और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि खुद को सीबीआई का डीआईजी बता कर राजीव सिंह नाम के इस शख्स ने किन-किन लोगों से क्या-क्या फायदा उठाया और कहीं उसके तार किसी बड़ी साजिश से तो जुड़े नहीं हैं? मामले की जांच जारी है।

अब मौसम फिर होगा ऑसम- इंडियन आइडल 2020 के साथ

मुंबई, (ब्यूरो)। सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडियन आइडल का 12वां सीजन शुरू करने जा रहा है, जो छोटे परदे पर बेमिसाल आवाजों का टैलेंट पेश करने वाला सबका चहेता मंच है। फ्रीमैंटल मीडिया के निर्माण में बना इंडियन आइडल सीजन 12, आगामी 28 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे टीवी लवर्स को रिझाने आ रहा है। इस साल की शो की थीम है, अब मौसम फिर होगा ऑसम।

जजों के पैनल ने ऑडिशन में पहुंचे जबर्दस्त टैलेंटेड प्रतिभागियों में से कुछ आवाजें चुनी हैं। इस पैनल में मशहूर गायक एवं म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी, पॉपुलर सिंगर एवं यूथ आइकॉन नेहा कक्कड़ और सभी के चहेते हिमेश रेशमिया शामिल हैं।

नए सीजन के होस्ट होंगे आदित्य नारायण

इंडियन आइडल में देश के कोने-कोने से आया म्यूजिकल टैलेंट देखने को मिलेगा। जब हफ्ते दर हफ्ते दर्शक व जज अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को समर्थन देंगे और उन्हें वोट करेंगे, तो टॉप 15 प्रतिभागियों के बीच मुकाबला भी कड़ा होता चला जाएगा, जब तक कि देश को अगला इंडियन आइडल नहीं मिल जाता। सुशील और सुरीले आदित्य नारायण नए सीजन के होस्ट होंगे।

सुरक्षा — अब और मजबूत होगी भारत की ताकत

स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की जल्द टेस्टिंग करेगा तेजस

नई दिल्ली ■ एजेंसी

लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में वायुसेना एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र का परीक्षण स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए किया जाएगा।

मिसाइल का ग्राउंड ट्रायल हो चुका है पूरा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेट सुखोई के बाद सभी मौसम में इस्तेमाल होने वाली अस्त्र मिसाइल का ग्राउंड ट्रायल पूरा हो चुका है। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का फ्लाइट ट्रायल अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ की योजना 160 किमी की रेंज के साथ अस्त्र के मार्क-2 संस्करण का परीक्षण शुरू करने की भी है।

पहली स्वदेशी मिसाइल की खूबियां

- ये दुनिया की बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टु एयर मिसाइलों में से एक है।
- 3.57 मीटर लंबी और 154 किलो वजनी अस्त्र मिसाइल ध्वनि की गति से 4.5 गुना तेज रफ्तार से दुश्मनों के टारगेट पर प्रहार करने में सक्षम है।
- इस मिसाइल की विशेषता है कि दुश्मन से चौतरफा घिरने की स्थिति में यह एक साथ कई टारगेट पर निशाना साध सकती है।
- ये आंखों से दिखाई न देने वाले लक्ष्य को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है।
- मिसाइल का 2003 से 2019 तक अलग-अलग लेवल पर 29 बार टेस्ट हो चुका है।

तेजस की खासियत

- यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' है, जिसे 'विमान विकास एजेंसी' तथा 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह सबसे छोटे-हल्के वजन का एकल इंजन युक्त एक सामरिक लड़ाकू विमान है।
- इसे रूस के एमआईजी-21 लड़ाकू विमानों पर अपनी निर्भरता को कम करने तथा स्वदेशी युद्ध संबंधी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

विस्कॉन्सिन मॉल गोलीबारी में एक संदिग्ध गिरफ्तार

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मॉल में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। वुवातोसा पुलिस विभाग ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। गत शुक्रवार को वुवातोसा के मेफेयर मॉल में एक संदिग्ध ने गोलीबारी की थी, जिसमें आठ लोग घायल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी ने शुरुआत में संदिग्ध की पहचान 20 से 39 वर्ष के बीच एक अंग्रेज व्यक्ति के रुप में की थी।

आठ लोग हुए थे घायल

पुलिस प्रमुख बैरी एम वेबेर ने बताया कि वुवाकोसा पुलिस विभाग ने मॉल गोलीबारी मामले में 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त संदिग्ध के पास से उस हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक भी बरामद हुई है। वेबेर ने हालांकि इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि हथियार किस प्रकार का था और संदिग्ध की गिरफ्तारी पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। वाओवातोसा के मेयर डेनिस मेकब्राइड ने कहा कि वारदात के बाद संदिग्ध मॉल में ही था।

पंजाब सरकार द्वारा 8393 रेगुलर अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी

प्री -प्राईमरी कक्षाओं के लिए पक्के अध्यापक भर्ती करने वाला पहला राज्य बनेगा पंजाब - विजय इंदर सिंगला

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से बीते दिनों स्मार्ट स्कूल मुहिम के समागम के दौरान प्री-प्राईमरी कक्षाओं के लिए रेगुलर अध्यापकों की नियुक्ति करने के ऐलान को अमली रूप देते हुये पंजाब सरकार द्वारा 8393 अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब श्री विजय इंदर सिंगला ने और ज्यादा जानकारी देते हुये बताया कि देश के पहले राज्य के तौर पर नवंबर 2017 में शुरू की गई प्री-प्राईमरी कक्षाओं को पक्के अध्यापक देने के लिए 8393 पद नोटीफायी करने के उपरांत शिक्षा भर्ती डायरैक्टोरेट पंजाब अधीन जनतक नियुक्तियों के अंतर्गत 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदनों की माँग कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्री-प्राईमरी कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों में पक्के अध्यापक भर्ती करने वाला पंजाब देश भर में से पहला राज्य बन जायेगा।

कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि इस भर्ती का एक अन्य बड़ा पक्ष यह है कि शिक्षा विभाग में लम्बे अरसे से कार्यशील शिक्षा प्रोवाईडरों, एजुकेशन प्रोवाईडरों, एजूकेशन वालंटियरों, ई.जी.एस. वालंटियरों, ए.आई.ई. वालंटियरों और एस.टी.आर. वालंटियरों को रेगुलर अध्यापक बनने का भी सुनहरा मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि इन वालंटियरों को इस भर्ती में आयु समी की विशेष छूट दी गई है। श्री सिंगला ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 3से 6साल तक के बच्चों के लिए प्री-प्राईमरी शिक्षा तीन साल पहले आरंभ की गई थी, जिसके बहुत ही सार्थक नतीजे सामने आए हैं। इसके अंतर्गत प्री-प्राईमरी शिक्षा के मानक में

विस्तार करने हेतु पंजाब सरकार की तरफ से प्री-प्राईमरी अध्यापकों की भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है जिससे छोटे बच्चों के लिए पक्के अध्यापकों की माँग को पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मानक सुधार लाने के लिए बड़े स्तर पर यत्न किये जा रहे हैं और अब सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी भी नहीं रहने दी जायेगी। भर्ती बोर्ड डायरैक्टोरेट की तरफ से जारी पत्र के अनुसार शैक्षिक योग्यता में बारहवीं या इसके बराबर की परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर ऐजूकेशन प्रोग्राम या इसके बराबर का कोई अन्य कोर्स किया हो, के साथ दसवीं में पंजाबी लाज़िमी या चुनिंदे विषय के तौर पर परीक्षा पास की हो निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18से 37 आयु रखी गई है परन्तु शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षा प्रोवाईडरों, एजूकेशन प्रोवाईडरों, एजूकेशन वालंटियरों, ई.जी.एस. वालंटियरों, ए.आई.ई. वालंटियरों, एस.टी.आर. वालंटियरें को आयु की ऊपरी सीमा में की गई सेवा के बराबर छूट दी गई है। तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। कैटागरी वाइज़ पोस्टों के अंतर्गत 8393 पोस्टों में से जनरल 3273, अनुसूचित जाति (एम और बी) 840, अनुसूचित जाति (आर और ओ) 839, अनुसूचित जाति (पूर्व फ़ौजी)(एम और बी) 168, अनुसूचित जाति (पूर्व फ़ौजी)(आर. और ओ) 168, अनुसूचित जाति (खिलाड़ी)(एम और बी) 42, अनुसूचित जाति (खिलाड़ी)(आर और ओ) 42, पिछड़ी श्रेणियां 839, पिछड़ी श्रेणियां (पूर्व फ़ौजी) 168, खिलाड़ी (जनरल) 167, स्वतंत्रता सेनानी 84, पूर्व फ़ौजी (जनरल) 588, अपंग वर्ग के अंतर्गत वीज़ुअली इम्पेअरड, हियरिंग इम्पेयर, ओरथोपैडीकली डिसएबलड और इंटैलैकचुअली डिसएबिलीटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी वर्गों के लिए 84-84, जनरल श्रेणी के इकनामीकली वीकर सैक्शन के लिए 839 पद आरक्षित किये गये हैं।

कालेजों के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटियों और विद्यार्थी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा-डीसी

विद्यार्थियों के कल्याण को विश्वसनीय बनाने की वचनबद्धता को दोहराया

■ जालंधर/रवि

डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने मंगलवार को कहा कि विद्यार्थियों के कल्याण को विश्वसनीय बनाने वाले सभी मुद्दों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए प्रिंसिपल एवं यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों की संस्था की एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा।

जिला प्रशासकीय कंपलैक्स के कांफ्रेंस हाल में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों और अलग-अलग कालेजों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि विद्यार्थियों और प्रिंसिपल द्वारा उठाई गई समस्याएँ और मुद्दों पर विचार किया गया है।

उन्होंने कहा कि वह इन मुद्दों के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ के उच्च आधिकारियों को एक विस्तारित रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही इन मुद्दों का निपटारा कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति का गठन एक दिन के भीतर कर दिया जायेगा और यूनिवर्सिटी की परीक्षा फीस समेत अन्य मुद्दे बिना किसी देरी के हल कर दिए जाएंगे। थोरी ने कहा कि विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 25 नवंबर को शुरू किये जाने की आशा है जिससे वह नई लांच की गई डा. बीआर अम्बेदकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार विद्यार्थियों के कल्याण हेतु वचनबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि विद्यार्थियों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलने को विश्वसनीय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा क्योंकि राज्य सरकार इस योजना को हर कीमत पर लागू करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होने शैक्षिक संस्थाओं को कहा कि वह विद्यार्थियों को किसी किस्म की परेशानी न आने दें। इससे पहले प्रिंसिपल और विद्यार्थियों ने डिप्टी कमिश्नर को उनको आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है। इस अवसर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह, एस डी एम राहुल सिन्धु और डा जयइंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जालंधर के संघा चौक में रेडीमेड गारमेंट शोरूम में लाखों की चोरी

■ जालंधर/रवि

जालंधर शहर में चोरों के हौंसले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसा ही मामला सुबह के समय शहर के महानगर के संघा चौक में रेडीमेड गारमेंट शोरूम से चोर लाखों के कपड़े चुरा कर ले गए। दुकान के मालिक वरुण ने

बताया कि उन्होंने करीब डेढ़ महीने पहले मॉडर्न मैन नाम से शोरूम खोला है दुकान में उन्होंने अलग-अलग वैरायटी के कपड़े रखे हुए हैं। आज सुबह जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे हुए थे।

उन्होंने अंदर जाकर देखा तो करीब 5 लाख के कपड़े और गल्ले से 20 हजार का कैश गायब था वरुण ने बताया कि दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बेलैरो सवार चोर दुकान से माल चुरा कर ले गए। इस घटना की सूचना इलाके के पास पड़ते पुलिस स्टेशन में दी गई है अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कब तक लुटेरों को अपनी हिरासत में लेती हैं।

नगर-निगम के प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में वित्तीय और ठेका कमेटी की मीटिंग

■ जालंधर/रवि

मेयर जगदीश राजा की अध्यक्षता में हुई जिसमें नगर-निगम कमिश्नर करनेश शर्मा, पार्षद बंटी नीलकंठ, ज्वाइंट कमिशनर हरचरण सिंह, पार्षद ज्ञान चंद व अन्य नगर-निगम मुलाजिम भी उपस्थित थे। इस मीटिंग में लगभग 18 करोड़ के काम पास किए गए है।

स्पोर्ट्स प्लैनट

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने का कारनामा किया है। विराट भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान हैं।

क्या भारतीय क्रिकेट के लिए विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं रोहित शर्मा?

•नई दिल्ली/ब्यूरो

विराट कोहली ने जब से भारतीय टीम के लिए कप्तानी की है वो टीम इंडिया को एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जिता सके हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी इतना ही सच है कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया दिन प्रति दिन बेहतर होती गई है। भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग सुनने को मिल रही है। क्रिकेट के फैंस हो या फिर पूर्व क्रिकेटर हर कोई चाह रहा है कि भारत के सफेद गेंद क्रिकेट में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम इंडिया के लिए किसी एक प्रारूप में कप्तान बना दिया जाना चाहिए। रोहित ने इस साल अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को पांचवी बार चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा ने साल 2013 में अपनी टीम की कप्तानी संभाली और मानो जब से मुंबई इंडियंस की किस्मत पलट गई। टीम अबतक पांच बार चैंपियन बन चुकी है। रोहित के आईपीएल में सफलता को देखकर ही टीम इंडिया में भी उन्हें कप्तान बनाने की मांग हो रही है। ऐसे में बीसीसीआई के सामने अब बड़ा संकट आ गया है कि क्या रोहित शर्मा को किसी एक प्रारूप की कप्तान दें या फिर विराट कोहली के साथ ही आने वाले समय में कप्तान के तौर पर आगे बढ़े। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बनने का सही विकल्प है या फिर ऐसा करना टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। रोहित शर्मा के लिए कई पूर्व क्रिकेटरों ने बयान दिए है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा भारत के कप्तान नहीं बनते हैं तो इससे भारत का नुकसान होगा ना कि रोहित का बेशक एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिर एक कप्तान को परखने का क्या पैमाना होता है। आपको किसी को परखने का पैमाना एक ही रखना होगा। रोहित ने अपनी टीम को पांच बार आईपीएल खिताब जिताया है। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि बिना किसी सवाल के रोहित शर्मा को भारत के टी-20 टीम का कप्तान बनना चाहिए। वह एक शानदार कप्तान हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि टी-20 मैच कैसे जीते जाते हैं। इससे कोहली को बतौर खिलाड़ी खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। रोहित भारत में टी-20 फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के कई देशों में खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट की कप्तानी करते हैं।

क्या कप्तान के तौर पर रोहित विराट से बढ़िया विकल्प साबित होंगे?

विराट कोहली ने जब से भारतीय टीम के लिए कप्तानी की है वो टीम इंडिया को एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जिता सके हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी इतना ही सच है कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया दिन प्रति दिन बेहतर होती गई है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने का कारनामा किया है। विराट भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान हैं। अगर विराट कोहली के कप्तानी रिकार्ड की

बात करें तो विराट ने अब तक भारत के लिए वनडे में 89 मैचों में कप्तानी की है जहां उन्होंने 62 मैचों में जीत हासिल की है और 24 में उन्हें हार मिली है। इस दौरान विराट का जीत प्रतिशत 71.83 का रहा है। वहीं विराट ने 55 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें उन्होंने 33 मैच जीते हैं। इसके अलावा विराट ने 37 टी-20 मैचों में कप्तानी करते हुए 24 मैचों में जीत हासिल की है। साफ है विराट कोहली के अगर कप्तानी में आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह दर्शाते है कि विराट ने अबतक किसी भी मामले में में खराब काम नहीं किया है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल तक का सफर तय किया था। इसके अलावा टीम ने 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके अलावा अगर रोहित शर्मा को जब भी कप्तानी करने का मौका मिला है तो उन्होंने भी टीम इंडिया को सफलता ज्यादा दिलाई है। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 10 मैचों में कप्तानी की है जिसमें 8 में जीत और 2 मैचों में हार मिली है। रोहित ने अपनी कप्तानी में साल 2018 में टीम इंडिया को एशिया कप का खिताब भी जिताया था। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर विराट कोहली ने कप्तानी में कुछ खराब प्रदर्शन किया हो तो उन्हें हटाया जा सकता था। लेकिन अब जब सामने 2021 टी-20 वर्ल्ड कप खड़ा हो जिसका आयोजन भारत में होना है। ऐसे में टीम इंडिया कप्तान बदलकर रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में लंबे समय से अलग-अलग फार्मेट में कप्तान रखने का नियम चलता रहा है। लेकिन अब यह जानना भी दिलचस्प है कि क्या भारत में ये फार्मूला काम सकता है। क्योंकि यह हर कोई जानता है कि भारत में अगर खिलाड़ियों के साथ दो कप्तान रहेंगे तो ड्रेसिंग रूम के माहौल में गर्मागर्मी आ सकती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत को 1983 में पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव का मानना है कि विराट कोहली वर्तमान में तीनों प्रारूपों में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी में आप दो सीईओ बनाते हैं? अगर कोहली टी 20 खेल रहे हैं और वह काफी अच्छे हैं। उसे वहीं रहने दो। हालांकि मैं अन्य लोगों को बाहर आते देखना चाहूंगा, लेकिन यह मुश्किल है। हमारी तीनों फॉर्मेट की 70-80 प्रतिशत टीम एक ही टीम है। उन्हें अलग-अलग सिद्धांत वाले कप्तान पसंद नहीं हैं। यह उन खिलाड़ियों के बीच अधिक अंतर ला सकता है जो कप्तान की ओर देखते हैं। अगर आपके पास दो कप्तान हैं, तो खिलाड़ी सोच सकते हैं कि वह टेस्ट में मेरा कप्तान बनने वाला है। मैं उसे नाराज नहीं करूंगा। जाहिर है कपिल देव की बात बिल्कुल सही भी है।

वैसे भी विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने बढ़िया खेल दिखाया है। अब अगर विराट 2021 में भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में नाकामयाब साबित होते हैं तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है।

आंगनवाड़ी मुलाजिमों और वर्करों के आश्रितों की तरस के आधार पर नियुक्ति संबंधी शर्तों में छूट-अरुणा चौधरी

वर्कर और हैल्पर एक्स ग्रेशिया के लिए भी 60 साल की आयु के बाद ही कर सकेंगी दावा पेश

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्करों के आश्रितों को तरस के आधार पर नौकरी सिर्फ़ विधवा बहु को देने वाली शर्त को हटाने का ऐलान करते हुये वर्करों और हैल्परों की सभी जायज़ माँगें मानने का भरोसा दिया है। आज यहाँ सिविल सचिवालय में अपने दफ़्तर में तीन आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर्ज़ यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान श्रीमती चौधरी ने कहा कि तरस के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी मौजूदा शर्त सिर्फ़ विधवा बहु को पहल देना है, जिसको अब बदल कर कोई भी आश्रित किया जायेगा। वर्करों और हैल्परों को एक्स ग्रेशिया पहले 70 साल की आयु बाद मिलता था, जबकि सेवा मुक्ति की आयु 65 साल थी। अब वर्कर और हैल्पर एक्स ग्रेशिया के लिए 60 से 65 साल की आयु तक कभी भी दावा पेश कर सकती हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आंगनवाड़ी हैल्परों से आंगनवाड़ी वर्करों की तरक्की सम्बन्धी ग्रैजूएशन की शर्त को भी घटा कर 12वीं पास के साथ पाँच साल का तजुर्बा कर दिया गया है। वर्करों को स्मार्ट फ़ोन देने की माँग पर उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी देरी केंद्र सरकार की तरफ से फोनों की खरीद सम्बन्धी मापदंड तय न करने के कारण हुई है, जिस कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। जैसे ही तयशुदा मापदंड भारत सरकार से प्राप्त होंगे, खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। आंगनवाड़ी सेंटरों में बुनियादी सहूलतों संबंधी बात करते हुये उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के सभी सेंटरों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सहूलतें दिसंबर 2020 के अंत तक मुहैया करवा दी जाएंगी।

श्रीमती अरुणा चौधरी ने आंगनवाड़ी सेंटरों की इमारतों के किराये का मामला भी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की जगह अपने हाथ में लेने के लिए भी हल करने की बात कही। यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग तीन घंटे चली मीटिंग के दौरान उन्होंने पोषण अभियान के अधीन आंगनवाड़ी वर्करों को 'प्रदर्शन प्रेरक राशि' (परफॉरमेंस इनसैंटिव) जल्द जारी करवाने संबंधी कहा। उन्होंने कहा कि नये मुख्य आंगनवाड़ी सैंटर मंज़ूर होने के बाद मिनी आंगनवाड़ी सैंटरों को मुख्य आंगनवाड़ी सेंटरों में तबदील किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ योजना के फार्म भरवाने के लिए 100 रुपए प्रति वर्कर और 50 प्रति हैल्पर देने का भी ऐलान किया। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि जून 2020 में बजट प्राप्त हुआ था, जो समूह ज़िला प्रोग्राम अफ़सरों को बाँट दिया गया। उनकी तरफ से बनते समय के मान भत्तों की अदायगी कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से पिछले समय की पैंडिंग लायबिलटी प्राप्त हो गई है, जल्द बजट का वितरण कर दिया जायेगा।

3 से 6साल के बच्चों का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्र में यकीनी बनाने और प्राईमरी स्कूलों से बाहर प्राईवेट इमारतों में चल रहे आंगनवाड़ी सैंटरों को स्कूलों में तबदील करने का मुद्दा स्कूल शिक्षा मंत्री के पास उठा कर हल करवाने का भरोसा दिया।

जालंधर तहसील कॉम्प्लेक्स में पटवारी को रिशवत लेते विजीलैंस ब्यूरो टीम ने किया काबू

■ जालंधर ब्रीज/रवि

जालंधर तहसील कॉम्प्लेक्स में आज विजीलैंस ब्यूरो टीम ने छापेमारी कर पटवारी नरिंदर कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया। दिलजिंदर सिंह ढिल्लो सीनियर अफसर विजीलैंस ब्यूरो ने बताया की उनके पास इसकी शिकायत तिथि 18-11-2020 को विजीलैंस ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-1800-1000 पर अमनदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह की तरफ से की गई जिसके

आधार पर विजीलैंस ब्यूरो टीम ने नरिंदर गुप्ता को आज अमनदीप सिंह से 2000 रिशवत लेते काबू किया। विजीलैंस ब्यूरो के डी.एस.पी दलबीर सिंह ,सब इंस्पेक्टर,गुरुबख्श सिंह, सब इंस्पेक्टर जगीरी लाल, ए.एस.आई गुरजीत सिंह, ए.एस.आई संजीव कुमार, ए.एस.आई रणजीत सिंह, मुख्य सिपाही तीर्थ सिंह, सीनियर सिपाही अमनदीप मान पटवारी नरिंदर कुमार को रिशवत लेते रंगे हाथ काबू किया। पटवारी नरिंदर कुमार पर मुकदमा नंबर 16 तिथि 23-11-2020 धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया । इसी दौरान पटवारी नरिंदर कुमार के घर की तलाशी ली गई जिसमें 4,29,000 रुपए की नगदी और जरूरी दस्तावेज़ बरामद किए गए। इस कारवाई में विजीलैंस ब्यूरो के डी.एस.पी दलबीर सिंह ,सब इंस्पेक्टर,गुरुबख्श सिंह, सब इंस्पेक्टर जगीरी लाल, ए.एस.आई गुरजीत सिंह, ए.एस.आई संजीव कुमार, ए.एस.आई रणजीत सिंह, मुख्य सिपाही तीर्थ सिंह, सीनियर सिपाही अमनदीप मान आदि मौजूद थे ।

पंजाब के परिवहन विभाग द्वारा धुंध बढ़ने के मद्देनज़र एडवायज़री जारी

वाहन चालकों को अपील- सड़कीय नियमों की पालना की जाये

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के परिवहन विभाग द्वारा सर्दियों के मौसम के दौरान धुंध बढ़ने के मद्देनज़र वाहन चालकों के लिए एक एडवायज़री जारी की है जिससे सड़क दुर्घटवानों को रोका जा सके। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक प्रवक्ता ने बताया कि सर्दियों के मौसम में धुंध के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएँ बढ़ जाती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम को ध्यान में रखते हुए आम जनता से अपील है कि धुंध में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहन चालक मौसम के पूर्व अनुमान की जांच करने के उपरांत ही यात्रा पर निकलें। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालक अपने वाहनों की अच्छी हालत के साथ-साथ हैडुलाईट, टेल लाईट, फोग लाईट, इंडीकेटर और रिफलेक्टर सहित ब्रेक, टायर, विंड स्क्रीन वाईपर, बैटरी और कार हीटिंग व्यवस्था को भी चालू हालत में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपील की कि ज़्यादा धुंध की चेतावनी पर यात्रा को मौसम साफ़ होने तक टालने की कोशिश की जाये। प्रवक्ता के अनुसार वाहन चालक धुंध में वाहनों को लौ-बीम पर चलाएं क्योंकि धुंध के दौरान हाई-बीम कारगर नहीं होता। उन्होंने बताया कि धुंध के दौरान फोग लाईटों, गाड़ीयों की निर्धारित स्पीड और वाहनों में उचित दूरी रखी जाये और सड़कों पर अंकित सफ़ेद पट्टियों को एक मार्ग दर्शक के रूप में ध्यान में रखते हुए वाहन चलाया जाये। वाहनों के शीशे उचित मात्रा तक नीचे रखे जाएँ और संकट स्थिति में यदि वाहन को रास्ते में रोकना पड़े तो जहाँ तक संभव हो वाहन को सड़क से नीचे उतार कर खड़ा किया जाये। धुंध में वाहन चलाते हुए गैर-ज़रूरी ओवरटेकिंग न की जाये, लेन न बदली जाये और भीड़ वाली सड़कों पर वाहन को रोकने से बचा जाये।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.